Hitch of India

ग्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—ज्ञा 3—उपलब्द (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं > 271]

नई विस्ती, शुक्रवार, जून 21, 1974/पर्यंट 31, 1896

NJ. 271]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 1974/JYAISTHA 31, 1896

इस भार में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सबे।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June 1974

Subject.—Procedure for Indenting and Despatch of Iron and Steel.

- S.O. 377(E)/ESS. COMM/IRON AND STEEL.—In exercise of the powers confessed by clause 17A of the Iron and Steel (Control) Order, 1956 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Heavy Engineering No. S.O. 1566, dated the 7th April, 1971, the Central Government hereby makes the following directions regarding the procedure to be followed in the placing of orders on producers or stockists of iron and steel and the despatch of the same, namely:—
- 1. All indentors requiring iron and steel for genuine purposes will approach the Joint Plant Committee set up by the Central Government under the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Heavy Engineering No. SC(I)-1(5)/71-B dated the 7th April, 1971 for planning their indents on producers subject to such limits, regulations, conditions that the Joint Plant Committee may prescribe from time to time.
- 2. The indents presented to the Joint Plant Committee shall be accompanied by such documents as may be prescribed by that Committee to satisfy the Committee that the indentor is a party authorised or competent to utilise the particular category of iron or steel for any genuine use in construction or fabrication

- 3. The Joint Plant Committee may reject any indent or alter the size/sections/tonnages indented for according to the criteria laid down by the Joint Plant Committee from time to time. In laying down such criteria, the Joint Plant Committee will take into consideration the Rolling Programmes of producers, availability of sections/categories, backlogs of old allocations and the quantum and genuineness of the consumers' demands.
- 4. In respect of those categories of iron and steel which one within the purview of the Steel Pritority Committee set up by the Central Government under the notification aforesaid, consumers who have orders booked with the main producers and who are interested in getting priority for delivery during any specified period should approach that Committee through their sponsoring authorities or in the manner prescribed by the above committee from time to time.
- 5. The priority allocations will be made six-monthly. Steel fabricating units whose requirements do not vary very much from period to period will be free to give their annual requirements at the beginning of each financial year instead of applying six-monthly.

[No. SC(I)-1(3)/74] V. K. DAR, Jt. Secy.

इस्पात ग्रीर लान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

ग्रधिमूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1974

[क्षय.--लोहें श्रीर इस्पात के लिए मांगपत्र भेजने श्रीर उसके प्रेषण की प्रक्रिया ।

- का० आ० 397(म्)/मादश्यक यस्तु/लोहा और इस्पात. केन्द्रीय सरकार लोहा और इस्पात (नियंत्रण) भादेण 1956, के खण्ड 17-क द्वारा प्रदत्त शिवसयों का प्रयोग करते हुये तथा भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और भारी इजीनियरी मंद्रालय की मधिसूचना स० का० आ० 1566 तारी ख 7-4-1971 को अधिकान्त करते हुए लोहे और इस्पान के उत्पादकों अथवा स्टाकिस्टों को आईर देने और उसके प्रेषण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया की बाबत निम्नलिखित निदेश करती है, अर्थात:—
- 1. सभी मागकर्ना जिन्हें वास्तविक प्रयोजनों के लिए लोहे और इस्पात की श्रपेक्षा है, भारत सरकार के इस्पात श्रोर भारी इंजीनियरी मंत्रालय की श्रिधसूचना सं० एस० सी० (1)-1(5)/71—बी, तारीख 7 श्रप्रैल 1971 के श्रधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित संयुक्त संयंत्र समिति को ऐसी परिसीमाश्रों, विनियमों, शर्तों के श्रधीन रहते हुए जो सयुक्त संयंत्र समिति द्वारा समय समय पर विहित्त की जाए, उत्पादकों को श्रपन मागपत्र भंजने के लिए लिखेंगे।
- 2. संयुक्त संयंत्र समिति को पेश किए गए मागपतों के साथ ऐसे दस्सावेज रहेंगे जो उस सिमिति द्वारा विहित किए जाए जिससे कि सिमात का समाधान हो जाए कि मांगकर्ता एक प्राधिकृत पक्षकार या सिन्निर्माण या सरचना में किसी वास्तिवक प्रयोग के लिए विशिष्ट प्रवर्ग केलोहा या इस्पात का उपयोग करने के लिए सक्षम है।

- 3. संयुक्त संयंत्र समिति किसी मांगपत्र को ग्रस्वीष्ट्रत या संयुक्त संयत्न समिति द्वारा समय~समय पर श्रिष्ठिकथित मानदन्ड के श्रनुसार श्राशियत्त श्राकार/संक्शनों/टनमान को परिवर्तित कर सकेगी। ऐसे मानदन्ड ग्रिष्ठिकथित कर्ने में संयुक्त संयत्न सिमित उत्पादकों के बेलन कार्यक्रमों ग्रीर सेक्शनों/प्रवर्गों की उपलब्धि, पुराने श्रावटन के बकाया श्रीर उपभोक्ताश्रों की मांगों की मान्ना श्रीर उसकी वास्तविकता को ध्यान में रखेगी।
- 4. उन प्रवर्गों के लोहा और इस्पान की बाबन जो केन्दीय सरकार द्वारा उक्त अधि—
 सूचना के अधीन स्थापित इस्पान पूर्विकला समिति के क्षेत्र में आते हैं, वे उपभोक्ता जो मुख्य उत्पादकों
 को मांगपन्न भेज चुके हैं और किसी विनिर्दिष्ट अविध के भीतर परिदान की पूर्विकता पाने
 के लिए हितबद्ध हैं, उन्हें अपने प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से या उसरीति ; जो उक्त समिति
 द्वारा नमय—समय पर विहित की जाए, लिखना चाहिए।
- 5. पूर्विकता के आवंटन छमाही किए जाएंगे। इस्पात संरचना एकक जिनकी आव-भ्यकतार्थ श्रविधि से अविधि तक में परिवर्तित नहीं होती हैं, वे छमाही आवेदन करने के स्थान पर अन्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अपनी वार्षिक मांगों को देने के लिए स्वतन्त्र हैं।

[सं० एस० सी० (1)~1(3)/74] बी० के० दर, संयुक्त सचिव।

